

	<b>केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)</b>	
सत्यमेव जयते	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX, केंद्रीय कर शुल्क भवन, सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	7 <sup>th</sup> Floor, Central Excise Building, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
 079-26305065		टेलिफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(58)/12/EA-2/Ahd-I/2016-17 (9099 to 9063)  
Stay Appl.No. NA/2016-17

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-131-2017-18  
दिनांक Date : 27.10.2017 जारी करने की तारीख Date of Issue 23-11-17

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित  
Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Deputy Commissioner, Div-I, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, Ahmedabad-I द्वारा जारी मूल आदेश सं 91/Div-I/Rebate/2016-17 दिनांक: 22/12/2016, से सृजित

Arising out of Order-in-Original No. 91/Div-I/Rebate/2016-17 दिनांक: 22/12/2016 issued by Deputy Commissioner, Div-I, Central Excise, Ahmedabad-I

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent  
M/s Ashima Dyecot Pvt Limited  
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :  
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

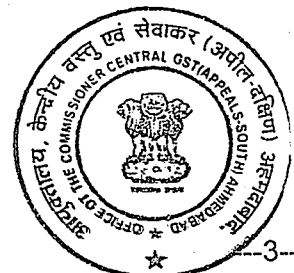
सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मेटल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This is a departmental appeal filed by Deputy Commissioner, Central Excise, Division I, Ahmedabad-I, on the basis of authorization granted by the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-I, vide Review order No. 12/2016-17 dated 07.03.2017. The departmental appeal is filed against OIO No. 91/Div-I/Rebate/2016-17 dated 22.12.2016 issued by the Deputy Commissioner, Central Excise, Division I, Ahmedabad-I, [in short – 'adjudicating authority'] in the case of M/s. Ashima Dyecot Private Limited, 'Texcellence Complex, Near Anupam Cinema, Khokhara, Ahmedabad- 380 021 [hereinafter referred to as 'Ashima'].

2. Briefly, the facts are that the adjudicating authority vide the impugned OIO sanctioned rebate of Rs. 1,33,444/- to M/s. Ashima. However, vide the aforementioned Review Order dated 7.3.2017, the impugned OIO was reviewed and this appeal has been filed on the below mentioned grounds:

- (a) that the refund sanctioning authority erred in sanctioning the rebate of Rs. 35,990/- out of Rs. 1,33,444/-, as the said amount was debited from the accumulated CENVAT credit of 4% Special Additional Duty (SAD) under section 3(5) of the Customs Tariff Act, 1975
- (b) that neither *the explanatory notes* nor the *JS/TRU's* letter have statutory backing;
- (c) that under *explanation 1* to para 3 of notification No. 19/2004-CE(NT) SAD does not find a mention under 'duty';
- (d) that in the case of Vinati Organics Limited [2014(311) ELT 994(GOI)], it was held that SAD paid on imported goods to counter balance sales tax, VAT, cannot be considered as duties of excise, eligible for rebate benefit;
- (e) that a similar view was held in Alpha Laboratories [2014(311) ELT 854(GOI)].

3. Personal hearing in respect of this departmental appeal was held on 13.9.2017, wherein Shri Nirav Shah, Advocate, appeared on behalf of M/s. Ashima. Shri Shah, Advocate explained the case and further provided a copy of OIA No. 27/2017-18 dated 21.7.2017 in the case of M/s. Ashima Limited.

4. I have gone through the facts of the case, the grounds in the departmental appeal and the arguments raised during the course of personal hearing. The question to be decided in this departmental appeal is whether the amount of 35,990/- out of Rs. 1,33,444/- sanctioned as rebate to M/s. Ashima, is correct or otherwise.

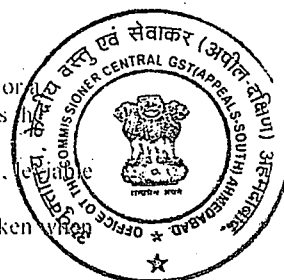
5. Before dwelling on to the dispute, I would like to reproduce the following for ease of reference:

CENVAT CREDIT RULES, 2004

RULE 3. CENVAT credit. — (1) A manufacturer or producer of final products or [provider of output service] shall be allowed to take credit (hereinafter referred to as CENVAT credit) of -

(i) the duty of excise specified in the First Schedule to the Excise Tariff Act, under the Excise Act ;

[Provided that CENVAT credit of such duty of excise shall not be allowed to be taken paid on any goods -



1

- (a) in respect of which the benefit of an exemption under Notification No. 1/2011-C.E., dated the 1st March, 2011 is availed; or  
 (b) specified in serial numbers 67 and 128 in respect of which the benefit of an exemption under Notification No. 12/2012-C.E., dated the 17th March, 2012 is availed:]  
 (ii) to (via)  
 (vii) the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, equivalent to the duty of excise specified under clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) [, (vi) and (via)]:  
[(viii) the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act

[emphasis added]

### CENTRAL EXCISE RULES, 2002

**RULE 18. Rebate of duty.** — Where any goods are exported, the Central Government may, by notification, grant rebate of duty paid on such excisable goods or duty paid on materials used in the manufacture or processing of such goods and the rebate shall be subject to such conditions or limitations, if any, and fulfilment of such procedure, as may be specified in the notification.

[*Explanation.* - For the purposes of this rule, "export", with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India and includes shipment of goods as provision or stores for use on board a ship proceeding to a foreign port or supplied to a foreign going aircraft.]

#### NOTIFICATION NO. 19/2004-CE(NT) [relevant extracts]

Rebate of duty for exports to countries other than Nepal and Bhutan — Procedure — Notification No. 40/2001-C.E. (N.T.) partially superseded

In exercise of the powers conferred by rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, notification No. 40/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June 2001, [G.S.R. 469(E), dated the 26th June, 2001] insofar as it relates to export to the countries other than Nepal and Bhutan, the Central Government hereby directs that there shall be granted rebate of the whole of the duty paid on all excisable goods falling under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), exported to any country other than Nepal and Bhutan, subject to the conditions, limitations and procedures specified hereinafter. -

*Explanation 1.* - "duty" for the purpose of this notification means duties of excise collected under the following enactments, namely :

- (a) the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (b) the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (c) the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978);
- (d) the National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), as amended by section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003) and further amended by section 3 of the Finance Act, 2004 (13 of 2004);
- (e) special excise duty collected under a Finance Act;
- (f) additional duty of excise as levied under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003);
- (g) Education Cess on excisable goods as levied under clause 81 read with clause 83 of the Finance (No. 2) Bill, 2004.

[emphasis added]

The rebate of excise duty on exported goods is granted under rule 18 of the Central Excise Rules, 2002. The procedure has been prescribed in notification No. 19/2004-CE(NT) dated 6.9.2004 in case of exports to countries other than Nepal. Now the notification, *ibid.*, the relevant extracts of which is quoted above, clearly states that there shall be granted rebate of the whole of the duty paid on all excisable goods falling under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, exported to any country other than Nepal and Bhutan.



subject to the conditions, limitations and procedures specified therein. The notification further vide its explanation I defines what "duty" would be for the purpose of rebate.

6. On examining the rebate claim in this back drop I find that

[a] M/s. Ashima has filed the rebate under notification No. 19/2004-CE(NT) dated 6.9.2004;

[b] M/s. Ashima has exported the goods on payment of duty from their CENVAT account. There appears to be no dispute as far as other conditions & limitations, laid down in the notification, except that M/s. Ashima, discharged the duty of Rs. 35,990/- before exporting the goods by debiting from CENVAT credit, the amount which was lying in the credit on account of 4% SAD. The main prayer in the departmental appeal is that the adjudicating authority erred in sanctioning the claim to the extent of Rs. 35,990/- because the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act did not find a mention in the explanation I of the notification.

7. Explanation I [reproduced above], clearly lists the duty on which rebate will be granted. It is nowhere mentioned in the impugned OIO that the rebate claim filed by the appellant is in respect of 4% SAD paid by the appellant. There is no doubt in my mind that the rebate claims are in respect of duties of excise paid under the Central Excise Act, 1944, before export of goods under rebate. This payment of duty of excise under Central Excise Act, 1944, clearly finds mention in (a) under Explanation I [extracts provided supra].

8. The departmental appeal further raises the contention that the rebate sanctioned to the tune of Rs. 35,990/- be set aside, as this amount was utilized towards payment of Central Excise duty from the amount standing to the CENVAT credit, under 4% SAD. Neither the notification nor the concerned central excise rule, put any bar in so far as utilization of CENVAT credit lying to the credit of 4% SAD is concerned. Though not directly relevant, I have reproduced the relevant extract of Rule 3 of the CENVAT Credit Rules, 2004 to primarily see whether the CENVAT credit availed in respect of duty paid in respect of 4% SAD was eligible as credit to M/s. Ashima. The relevant extracts, clearly shows that the availment of CENVAT credit by M/s. Ashima was correct. There is no bar on availment of CENVAT credit in respect of amount paid towards 4% SAD and there is also no bar towards utilization of the said CENVAT credit towards payment of duty for home clearance under the Central Excise Act, 1944. Then it is not understood, how duty paid towards clearance for the export should be treated differently? Therefore, the rejection of rebate claim by the adjudicating authority appears to be not tenable.

9. The departmental appeal has also relied upon the case Organics Limited [2014(311) ELT 994(GOI)] and Alpha Laboratories 854(GOI). I find that in the said case the rebates were filed under notification



CE(NT) dated 6.9.2004. The relevant text of the notification *ibid.* is reproduced below for ease of reference:

**NOTIFICATION NO. 21/2004-CE(NT) [relevant extracts]**

Rebate of duty on excisable goods used in manufacture/ processing of export goods — Procedure — Notification No. 41/2001-C.E. (N.T.) superseded

In exercise of the powers conferred by of rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, notification No. 41/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001 [G.S.R. 470(E) dated the 26th June, 2001], the Central Government hereby, directs that rebate of whole of the duty paid on excisable goods (hereinafter referred to as 'materials') used in the manufacture or processing of export goods shall, on their exportation out of India, to any country except Nepal and Bhutan, be paid subject to the conditions and the procedure specified hereinafter :-

*Explanation.* - "duty" means for the purposes of this notification, duties of excise collected under the following enactment, namely :-

- (a) the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (b) the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (c) the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978);
- (d) the National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), as amended by Section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003) and further amended by Section 3 of the Finance Act, 2004 (13 of 2004);
- (e) special excise duty collected under a Finance Act;
- (f) additional duty of excise as levied under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003);
- (g) Education Cess on excisable goods as levied under clause 81 read with clause 83 of the Finance (No. 2) Bill, 2004.

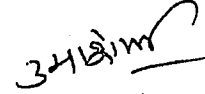
As is evident notification no. 21/2004, grants rebate of whole of the duty paid on excisable goods used referred in notification as 'materials', in manufacture/processing of export goods. The notification thereafter defines *duty* under explanation. There is a clear distinction between both the notifications issued under Rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 and both are for different purpose. While notification No. 19/2004-CE(NT) dated 6.9.2004 grants rebate on export of excisable goods, notification No. 21/2004, *ibid.* grants rebate on duty paid on excisable goods used in the manufacture/processing of export goods. Under notification No. 21/2004, no rebate can be claimed on materials used, in respect of 4% SAD, since the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, does not find a mention in the list of duties under explanation to the notification. Now to stretch this logic to notification No. 19/2004-CE(NT) dated 6.9.2004, when it clearly speaks of rebate of excise duty on exports of excisable goods on payment of duty under the Central Excise Act, 1944, is not a valid argument. Hence, the reliance on the case law is not tenable since it is not at all relevant to the present dispute.

10. In view of the foregoing, I find that adjudicating authority has correctly sanctioned the rebate to M/s. Ashima and hence, the departmental appeal is rejected. .

*[Signature]*



11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।  
11. The appeal filed by the department stands disposed of in above terms.




(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

Date 27.10.2017

Attested

  
(Vinod Lukose)  
Superintendent,  
Central Tax(Appeals),  
Ahmedabad.

By RPAD.

To.

M/s. Ashima Dyecot Private Limited,  
Texcellence Complex,  
Near Anupam Cinema,  
Khokhara. Ahmedabad- 380 021

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad Zone . .
2. The Principal Commissioner, Central Tax, Ahmedabad-I.
3. The Deputy/Assistant Commissioner, Central Tax, Division-I, Ahmedabad-I.
4. The Assistant Commissioner, System, Central Tax, Ahmedabad-I.
5. Guard File.
6. P.A.

